खंड १४ अंक ३ जुलाई २०१८

आरआईएस डायरी

–अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

एआईआईबी की वार्षिक बैठक से पहले और उसके दौरान अनेक कार्यक्रम

माननीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल *'बुनियादी ढांचे हेतु वित्त जुटाने के लिए नई तलाश'* नामक आरआईएस रिपोर्ट का विमोचन करते हुए। (बाएं से): बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी; महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस; उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत; और आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी।

इस तिमाही का समापन एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की वार्षिक बैठक पर आरआईएस के कार्यकलाप कार्यक्रम के साथ हुआ। देश भर में सात अलग–अलग स्थानों पर सात प्रमुख कार्यक्रम आरआईएस द्वारा विभिन्न विषयों पर आयोजित किए गए: बंदरगाह एवं तटीय बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना: संभावित क्षेत्रों पर एक प्रस्तुतीकरण (विशाखापत्तनम में 3–4 अप्रैल 2018 को); शहरी विकास: तकनीकी समाधान एवं गवर्नेंस संबंधी चुनौतियां (अहमदाबाद में 19–20 अप्रैल 2018 को); अत्याधुनिक, सुदृढ़ एवं डिजिटल बुनियादी ढांचा (बेंगलुरू में 3–4 मई 2018 को); क्षेत्रीय विकास के लिए भौतिक एवं सामाजिक बुनियादी ढांचा (गुवाहाटी में 14–15 मई 2018 को); स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा (भोपाल में 21 मई 2018 को); जल एवं स्वच्छता (पुणे में 31 मई और 1 जून 2018 को); और संसाधन जुटाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं नवाचार (मुंबई में 11 जून 2018 को)। प्रमुख विशेषज्ञों ने उपर्युक्त कार्यक्रमों के संबंधित विषयों पर तैयार गहन पृष्ठभूमि–पत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया।

श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार 'सुदृढ़ एवं बेहतरीन बुनियादी ढांचे के निर्माण' पर आयोजित एआईबीबी मेजबान देश सेमिनार में बोलते हुए।

बाएं से: सुश्री लाउरेल ऑस्टफील्ड, संचार प्रमुख, एआईआईबी; श्री शेषाद्री चारी, सदस्य, शासी परिषद, आरआईएस; प्रो. जगदीश मुखी, असम के माननीय राज्यपाल; श्री पी. डी. सोना, माननीय संसदीय सचिव (पर्यटन), अरुणाचल प्रदेश सरकार; श्री रवि कपूर, अपर मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, असम सरकार; और प्रो. अमिताभ कुंडू, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस 14–15 मई 2018 को गुवाहाटी में 'क्षेत्रीय विकास के लिए भौतिक एवं सामाजिक बुनियादी ढांचे' पर आयोजित लीड–अप कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में शिरकत करते हुए।

वार्षिक बैठक से पहले आयोजित किए गए उपर्युक्त सभी कार्यक्रम इन विषयों पर 'मेजबान देश में सेमिनार' के आयोजन के रूप में फलित हुए: बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण: अभिनव तरीकों एवं साझेदारी की तलाश (24 जून 2018 को); सहयोग एवं साझेदारी आगे बढ़ाना: विकसित होती रणनीतियां एवं सामूहिक कार्यकलाप और बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण करना: संसाधन जुटाना एवं नए साधनों की तलाश करना; भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के दृष्टिकोण पर मुख्यमंत्रियों के साथ पैनल परिचर्चा (25 जून 2018 को); संस्थानों, प्रौद्योगिकी एवं विधियों में नवाचारों को समाहित करना और सुदृढ़ एवं बेहतरीन बुनियादी ढांचे का निर्माण करना (26 जून 2018 को)। आरआईएस ने उपर्युक्त कार्यक्रमों के निष्कर्षों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक के दौरान 25 जून 2018 को मुंबई में माननीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 'बुनियादी ढांचे हेतु संसाधन जुटाने के लिए नई तलाश' नामक रिपोर्ट का विमोचन किया। इस दौरान महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस; उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत; बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी और भारत सरकार के माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पी. राधाकृष्णन की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। इस रिपोर्ट में कई नीतिगत सिफारिशों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सभी हितधारक उपयोगी मानेंगे।

सभी उपर्युक्त कार्यक्रमों और मेजबान–देश सेमिनारों का एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

श्री नारायण सिंह कुशवाहा, माननीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार 21 मई 2018 को भोपाल में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा पर आयोजित लीड–अप कार्यक्रम को संबोधित करते हुए।

श्री परमेश्वरन अय्यर, सचिव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार 31 मई और 1 जून 2018 को पुणे में जल और स्वच्छता पर आयोजित लीड–अप कार्यक्रम को संबोधित करते हुए।

श्री कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव (सागरमाला), शिपिंग मंत्रालय, भारत सरकार 3–4 अप्रैल 2018 को विशाखापत्तनम में 'बंदरगाह एवं तटीय बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना: संभावित क्षेत्रों पर एक प्रस्तुतीकरण' पर आयोजित लीड–अप कार्यक्रम को संबोधित करते हुए।

बाएं से: श्री राघव नेति, वरिष्ठ जल एवं स्वच्छता विशेषज्ञ; विश्व बैंक, प्रोफेसर एम.जी. चंद्रकांत, निदेशक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान; राजदूत एस.टी. देवारे, अध्यक्ष, शोध सलाहकार परिषद, आरआईएस; सुश्री जिंगमिन हुआंग, प्रधान शहरी विकास विशेषज्ञ, शहरी विकास एवं जल प्रभाग, एडीबी; और सुश्री नमिता विकास, समूह अध्यक्ष एवं वैश्विक प्रमुख– जलवायु रणनीति एवं उत्तरदायी बैंकिंग, यस बैंक 31 मई और 1 जून, 2018 को पुणे में जल और स्वच्छता पर आयोजित लीड–अप कार्यक्रम में शिरकत करते हुए।

एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक के साथ आरआईएस की सहभागिता

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत राजनीतिक नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास और सकारात्मक बदलाव के मार्ग पर सतत रूप से आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में स्वयं को भी शुमार करने की दिशा में अग्रसर है। आर्थिक विकास का विस्तृत होता क्षितिज विभिन्न क्षेत्रों में फैले कई स्तरों पर बुनियादी ढांचे के मजबूत वित्त पोषण पर काफी हद तक निर्भर है। बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास से औद्योगिक पुनरुद्धार और सतत विकास की परस्पर जरूरतें पूरी होंगी। समावेशी विकास की उभरती प्राथमिकताओं को साझेदारी एवं सहयोग, अभिनव वित्तपोषण, उद्यमिता और मजबूत कानूनी एवं संस्थागत ढांचे के जरिए आवश्यक सहारा दिया जाएगा। प्रौद्योगिकी पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से विकास की प्रक्रिया को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत सरकार ने 25–26 जून 2018 को मुंबई में एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की तीसरी वार्षिक बैठक की मेजबानी की। इस संबंध में आरआईएस ने भारत के अग्रणी उद्योग संगठनों फिक्की, सीआईआई और एसोचैम की अनुकरणीय साझेदारी के साथ ज्ञान साझेदार के रूप में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के संग मिलकर काम किया है। एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक से ठीक पहले आरआईएस ने संसाधन एवं संस्थागत चुनौतियों से पार पाने और कनेक्टिविटी तथा बुनियादी ढांचे के विकास से हो रहे लाभों में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों और सिविल सोसायटी संगठनों से भी सहयोग किया है। भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और एआईआईबी के अध्यक्ष श्री जिन लिक्यून ने नई दिल्ली में 27 फरवरी 2018 को आयोजित एक प्रभावशाली समारोह में औपचारिक रूप से एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक का शुभारंभ किया। श्री नितिन जयराम गडकरी, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और शिपिंग मंत्री तथा श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार ने नीति निर्माताओं, राजनयिकों, बैंकरों, बहुपक्षीय संस्थानों, उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के एक बड़े समूह के साथ अपनी ज्ञानविषयक परख या अंतर्दृष्टि साझा की थी।

आरआईएस ने 27 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में पूर्वावलोकन कार्यक्रम और मार्च–जून 2018 के दौरान आठ विषयगत संबंधित (लीड–अप) कार्यक्रमों को आयोजित करने में पूरी सक्रियता के साथ वित्त मंत्रालय से सहयोग किया था। संबंधित (लीड–अप) सम्मेलनों की थीम और शहर ये थेः कोलकाता में त्वरित जन परिवहन प्रणालियां; विशाखापत्तनम में बंदरगाह एवं तटीय बुनियादी ढांचा; अहमदाबाद में शहरी विकास; बेंगलुरू में अत्याधुनिक, सुदढ़ एवं डिजिटल बुनियादी ढांचा; गुवाहाटी में क्षेत्रीय विकास; भोपाल में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा; पुणे में जल एवं स्वच्छता; और मुंबई में 'संसाधन जुटाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं नवाचार'।

प्रत्येक संबंधित (लीड–अप) कार्यक्रम के लिए शहर का चयन इन कार्यक्रमों की संबंधित थीम के संदर्भ में उनके विशिष्ट योगदान और अहमियत को ध्यान में रखते हुए किया गया। उदाहरण के लिए, गुवाहाटी भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पूर्वोत्तर के साथ–साथ अन्य आकांक्षी क्षेत्रों में भी विशिष्ट बुनियादी ढांचे की कमी का उल्लेख बार–बार करता रहा है। इसी प्रकार, भारत के डिजिटल नेतृत्व के साथ–साथ नवाचार आधारित बदलावों में भी बेंगलुरू का एक विशिष्ट स्थान है और अत्याधुनिक, सुदढ़ एवं डिजिटल बुनियादी ढांचे पर हमारे विषयगत सम्मेलन के लिए उसका चयन किया जाना बिल्कुल सही है। उपर्युक्त कार्यक्रमों की संबंधित थीम पर गहन एवं व्यापक पृष्ठभूमि–पत्र प्रस्तुत करने के लिए अथक प्रयास किए गए, जिसमें योगदान देने के लिए प्रमुख विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। यह पृष्ठभूमि–पत्र हैंः त्वरित जन परिवहन प्रणालियों पर श्री राकेश रंजन द्वारा; बंदरगाह एवं तटीय बुनियादी ढांचे पर श्री विश्वपति त्रिवेदी द्वारा; शहरी विकास, डॉ. ओम प्रकाश माथुर द्वारा; समावेशी एवं सुदृढ़ बुनियादी ढांचे, प्रो. पार्थ मुखोपाध्याय द्वारा; डिजिटल बुनियादी ढांचे, डॉ. रजत कथुरिया द्वारा; क्षेत्रीय विकास, प्रो. सेबेस्टियन मॉरिस द्वारा; स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा, डॉ. अरुणव घोष और डॉ. कनिका चावला द्वारा; और जल एवं स्वच्छता, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर द्वारा।

प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के एक पैनल ने समय–समय पर आरआईएस की अनुसंधान टीम के साथ भी बातचीत की। इस पैनल में ये शामिल थेः डॉ. अतुल शर्मा, श्री रजत एम. नाग, डॉ. जगन शाह, श्री किशोर अरुण देसाई, डॉ. कविता अयंगर, श्री एस. के. दास, श्री अशोक खोसला, डॉ. दीपेन्द्र कपूर, डॉ. ललित कुमार, श्री सुरेश रोहिलिया, श्री अशोक खुराना, डॉ. इंदिरा खुराना, सुश्री ममता डैश, डॉ. ओम प्रकाश माथुर, प्रो. के.टी. रविंद्रन, डॉ. वाई. पी. आनंद, श्री शिवराज गुप्ता, डॉ. मिलन शर्मा, श्री प्रवीर पांडेय, श्री ए. जनार्दन राव, श्री समीर भटनागर, कैप्टन सुबेदार, कमोडोर सुजीत समादार, श्री सैबल के. डे और श्री आर.वी. वर्मा। आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग ने निरंतर मार्गदर्शन और अकादमिक अंतर्दृष्टि भी प्रदान की। डॉ. एम.एम. कुट्टी, विशेष सचिव; श्री समीर कुमार खरे, संयुक्त सचिव (फंड बैंक एवं एडीबी); डॉ. कुमार विनय प्रताप, संयुक्त सचिव (बुनियादी ढांचा, नीति एवं वित्त); सुश्री बंदना प्रेयसी, निदेशक (एमआई/आईएफ); श्री ऋषिकेश सिंह, निदेशक (एमआई); आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी ओर से पूर्ण सहयोग दिया। इसी तरह विभिन्न राज्य सरकारों और नीति आयोग, विदेश मंत्रालय एवं अन्य विभागों सहित केंद्र सरकार की एजेंसियों से सभी आवश्यक सहायता प्राप्त हुई। आरआईएस संबंधित (लीड–अप) कार्यक्रमों में फिक्की, सीआईआई और एसोचैम की साझेदारी के लिए आरआईएस सभी का आभारी है।

संबंधित (लीड–अप) कार्यक्रमों के आधार पर आरआईएस ने *'बुनियादी ढांचे हेतु वित्त जुटाने के लिए नई तलाश'* नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट आरआईएस की अनुसंधान टीम की व्यापक कड़ी मेहनत का नतीजा है जिसने उपर्युक्त कार्यक्रमों के सफल आयोजन की पूरी प्रक्रिया में भी योगदान दिया है। इस टीम ने आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत (डॉ.) मोहन कुमार और आरआईएस की अनुसंधान सलाहकार परिषद के अध्यक्ष राजदूत सुधीर देवारे के समग्र मार्गदर्शन में काम किया। डॉ. शेषाद्रि चारी, सदस्य, आरआईएस की शासी परिषद ने संबंधित (लीड–अप) कार्यक्रमों में व्यापक सहयोग दिया। आरआईएस की अनुसंधान टीम के सदस्यों में शामिल थेः डॉ. एस. के. मोहंती, प्रोफेसर; प्रो. अमिताभ कुंडू, प्रतिष्ठित फेलो; डॉ. प्रियदर्शी दाश, सहायक प्रोफेसर; डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर; श्री सुभोमय भट्टाचार्जी, परामर्शदाता; श्री अरुण एस. नायर, विजिटिंग फेलो, सुश्री गरिमा धीर, आईबीएसए फेलो; श्री सैयद मोहम्मद अली, रिसर्च एसोसिएट; और श्री वैभव कौशिक, अनुसंधान सहायक। हम आशा करते हैं कि नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, प्रोफेशनलों और हितधारकों को यह रिपोर्ट उपयोगी सिद्व होगी।

विकास के सतत लक्ष्य और सीएसआर एवं प्रमुख कार्यक्रमों के जरिए जीवन स्तर बढ़ाना

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) ने अनेक क्षेत्रों में कई पहल की हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी समावेशी विकास और सतत विकास सुनिश्चित करने वाले कई प्रमुख कार्यक्रम प्रक्षेपण किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में देश में क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव लाने की असीम क्षमता है। विशेषकर सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के एजेंडे के कारगर और लाभकारी कार्यान्वयन के लिए भारत द्वारा जताई गई प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया जाना है। इस संदर्भ में 'सीएसआर' की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है और भारत के समक्ष मौजूद विभिन्न सामाजिक–आर्थिक मुद्दों को हल करने के लिए इस मद में हो रहे योगदान पर चर्चा और समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है। यह बात रेखांकित की जाती है कि समावेशी विकास को मजबूत बनाने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआर योगदान को बढ़ाने की व्यापक गुंजाइश है। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आरआईएस ने एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक के दौरान 25 जून 2018 को मुंबई में रीच स्केल और एफआईडीसी के साथ मिलकर एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया।

'एसडीजी और सीएसआर एवं प्रमुख कार्यक्रमों के जरिए स्तर बढ़ाने' की थीम पर आयोजित सत्र का आरंभ आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के संबोधन के साथ हुआ। रीच स्केल के संस्थापक एवं सीईओ श्री डेविड विल्कॉक्स ने प्रारंभिक भाषण दिया। श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष भाषण दिया। सुश्री मेगन फॉलोन, सीईओ, बेयरफुट कॉलेज इंटरनेशनल; प्रो. अमिताभ कुंडू, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस; और श्री रविचंद्रन नटराजन, प्रमुख (साझेदारी एवं कॉरपोरेट संबंध), टाटा ट्रस्ट, मुंबई ने भी इस अवसर पर अपने–अपने विचार पेश किए। सत्र का समापन खुली परिचर्चा के साथ हुआ।

श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर तीसरा 'ईएएस'

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमपी और एनजी), भारत सरकार; राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन (एनएमएफ); और आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) के सहयोग से 8–9 जून 2018 को ओडिशा के भुवनेश्वर में समुद्री सुरक्षा एवं सहयोग पर तीसरा 'पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस)' का आयोजन किया। इस अवसर पर स्वागत भाषण आरआईएस स्थित एआईसी के समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने दिया। प्रारंभिक भाषण एनएमएफ के निदेशक वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान ने दिया, जबकि विशेष भाषण श्री अनुराग भूषण, संयुक्त सचिव (आसियान–एमएल) ने दिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार ने उद्घाटन भाषण दिया।

श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, श्री अनुराग भूषण, संयुक्त सचिव (आसियान–एमएल), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, वाइस–एडमिरल प्रदीप चौहान, निदेशक, एनएमएफ और डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर, आरआईएस एवं समन्वयक, आरआईएस स्थित एआईसी तीसरे ईएएस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शिरकत करते हुए।

ईएएस से जुड़े सदस्य देशों ने अपने यहां से अधिकारियों और विशेषज्ञों को नामांकित किया। इस दो दिवसीय सम्मेलन में लगभग 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन को पांच सत्रों में विभाजित किया गया, ताकि समुद्री सुरक्षा, समुद्री हिफाजत, समुद्र में सुव्यवस्था एवं नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) पर गहन चर्चा के साथ–साथ आगे की राह पर पैनल परिचर्चा भी संभव हो सके। आखिर में, श्री अनुराग भूषण, संयुक्त सचिव (आसियान–एमएल), एमईए ने समापन भाषण दिया और डॉ. प्रबीर डे ने धन्यवाद भाषण दिया। प्रतिनिधियों ने 8 जून 2018 को आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया और इसके साथ ही उन्होंने ओडिशा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से वाकिफ होने के लिए 9 जून 2018 को धौली एवं कोणार्क की शोध यात्राएं भी की थीं।

श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, श्री अनुराग भूषण, संयुक्त सचिव (आसियान–एमएल), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और वाइस–एडमिरल प्रदीप चौहान, निदेशक, एनएमएफ समुद्री सुरक्षा एवं सहयोग पर आयोजित तीसरे ईएएस सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए।

आसियान–भारत गैर–टैरिफ उपायों (एनटीएम) पर संगोष्ठी

आरआईएस स्थित आसियान–इंडिया सेंटर (एआईसी) ने 20 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली, भारत में आसियान इंडिया गैर–टैरिफ उपायों (एनटीएम) पर एक सेमिनार आयोजित किया। इस सेमिनार का आयोजन दरअसल आसियान और भारत के बीच एनटीएम पर एआईसी द्वारा किए गए शोध अध्ययन का नतीजा था। स्वागत भाषण डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर, आरआईएस और समन्वयक, आरआईएस स्थित एआईसी द्वारा दिया गया। आरंभिक भाषण श्री अनुराग भूषण, संयुक्त सचिव (आसियान–एमएल), विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार द्वारा दिया गया। अध्ययन पर प्रस्तुति डॉ. प्रबीर डे और डॉ. दुरइराज कुमारसामी दोनों ही द्वारा दी गई। प्रस्तुतियों के लिए टिप्पणियां श्री प्रणव कुमार, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं नीति प्रभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और डॉ. अनिल जौहरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी), नई दिल्ली से प्राप्त हुई। अंत में, डॉ. प्रबीर डे ने अध्ययन का सार प्रस्तुत किया और धन्यवाद ज्ञापन किया। संगोष्ठी में सरकारी अधिकारियों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों, उद्योग विशेषज्ञों, शोध विद्वानों इत्यादि ने भाग लिया।

आसियान–भारत गैर–टैरिफ उपायों (एनटीएम) पर आयोजित संगोष्ठी में अनेक प्रतिभागी।

आसियान के एचओएम के साथ 'दिल्ली वार्तालाप 10' पर परामर्श बैठक

आरआईएस ने 14 मई, 2018 को आसियान के एचओएम के साथ 'दिल्ली वार्तालाप 10' पर एक परामर्श बैठक आयोजित की। आरआईएस के चेयरमैन राजदूत डॉ. मोहन कुमार ने परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। श्री अनुराग भूषण, संयुक्त सचिव (आसियान–एमएल), विदेश मंत्रालय (एमईए) ने स्वागत भाषण दिया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने विशेष भाषण दिया। आरआईएस स्थित एआईसी के समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने 'दिल्ली वार्तालाप 10' पर एक प्रस्तुति दी। इसके बाद आसियान के एचओएम की ओर से टिप्पणियां प्राप्त हुईं। आखिर में डॉ. मोहन कुमार, चेयरमैन, आरआईएस ने सार प्रस्तुत किया और समापन भाषण दिया।

आसियान के एचओएम के साथ 'दिल्ली वार्तालाप 10' पर आयोजित परामर्श बैठक में अनेक प्रतिभागी।

इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

इंडोनेशिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने 19 अप्रैल, 2018 को राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस और प्रो. प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी और उनकी टीम के साथ एक संवादात्मक सत्र के लिए आरआईएस स्थित एआईसी का दौरा किया। यह संवादात्मक सत्र भारत, इंडोनेशिया एवं म्यांमार के बीच व्यापार तथा समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रीय सहयोग की भूमिका के लिए सहयोग के अवसरों और संभावनाओं के बारे में था।

इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल आरआईएस में।

विज्ञान कूटनीति कार्यक्रम का शुभारंभ

हाल के दशकों में विज्ञान कूटनीति विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर कर सामने आई है। इसका उपयोग उन वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में किया गया है जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समस्या की पहचान करने और उपयुक्त समाधान प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है। विज्ञान कूटनीति विकास सहयोग के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य देशों और समूहों के साथ सहयोग को गहन बनाने में सहायता कर रही है। आरआईएस ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (बेंगलुरू) के सहयोग से विज्ञान कूटनीति पर एक संयुक्त शोध कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की ओर से भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 7 मई 2018 को नई दिल्ली में किया गया था।

विज्ञान कूटनीति कार्यक्रम के शुभारंभ का उद्घाटन सत्र

आरआईएस के चेयरमैन राजदूत डॉ. मोहन कुमार ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने परियोजना की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। श्री टी. एस. तिरुमूर्ति, सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय ने मुख्य भाषण दिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और एसएंडटी मंत्रालय में सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने उद्घाटन भाषण दिया। प्रोफेसर डी. सुबा चंद्रन, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति एवं सुरक्षा अध्ययन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस), बेंगलुरू ने धन्यवाद ज्ञापन किया। विस्तृत एजेंडे को हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

'भारत का शहरी पुनरुत्थान' पर श्री हरदीप सिंह पुरी के साथ चर्चा

आरआईएस और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (एनआईयूए) ने 2 जून 2018 को नई दिल्ली में 'भारत के शहरी पुनरुत्थान' पर संयुक्त रूप से एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया। राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का आरम्भ आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ हुआ। प्रो. जगन शाह, निदेशक ने मुख्य प्रस्तुति दी। आवास एवं शहरी मामलों के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने मुख्य भाषण दिया। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों द्वारा खुली चर्चा करने के साथ इसका समापन हुआ।

श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार मुख्य भाषण देते हुए।

एसडीजी 2: 'सभी के लिए स्वस्थ भोजन सुनिश्चित करने हेतु टिकाऊ कृषि और किसानों की आय दोगुनी करना'–पर हितधारक कार्यशाला

आरआईएस सितंबर 2015 में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के उद्भव और उन्हें अपनाए जाने की प्रक्रिया के बाद से ही निरंतर इन लक्ष्यों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है। एसडीजी के प्रमुख कार्यकलाप कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आरआईएस विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया में एसडीजी के एजेंडे के प्रभावकारी कार्यान्वयन में जुटा रहा जिसके तहत एसडीजी के स्थानीयकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। आरआईएस ज्ञान साझेदारियों को मजबूत करने के लिए एसडीजी से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर भारत में प्रमुख प्रबुद्ध मंडलों (थिंक–टैंक) और संगठनों के साथ भी सहयोग कर रहा है। भारत सरकार का नीति आयोग भारत में एसडीजी के कार्यान्वयन में समन्वय और अगुवाई करने की दृष्टि से नोडल एजेंसी है। नीति आयोग, आरआईएस और संयुक्त राष्ट्र भारत द्वारा कई राष्ट्रीय एसडीजी परामर्श संयुक्त रूप से आयोजित किए गए; जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका एसडीजी के कार्यान्वयन के साथ–साथ एसडीजी के साथ तालमेल बैठाने और एसडीजी के स्थानीयकरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ताकि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों को प्रभावकारी ढंग से बेहतर किया जा सके।

इस श्रृंखला में 8 मई 2018 को नई दिल्ली में 'सभी के लिए स्वस्थ भोजन सुनिश्चित करने हेतु टिकाऊ कृषि और किसानों की आय दोगुनी करना – एसडीजी 2 के रोडमैप फ्रेमवर्क' पर एक दिवसीय हितधारक कार्यशाला आयोजित की गई। शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, सिविल सोसायटी संगठनों, केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, संयुक्त राष्ट्र संगठनों/निकायों के प्रोफेशनलों ने भारतीय संदर्भ में एसडीजी 2 की प्राप्ति की दिशा में अपनी आकांक्षाओं और प्रतिबद्धताओं को साझा किया। डब्ल्यूएफपी के सहयोग से आरआईएस द्वारा पेश की गई *'एसडीजी 2 रोडमैप फ्रेमवर्क'* नामक रिपोर्ट भी इस अवसर पर विमाचित की गई।

कार्यक्रम का आरम्भ नीति आयोग के सलाहकार डॉ. अशोक कुमार जैन के स्वागत भाषण के साथ हुआ। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने संदर्भ प्रस्तुत किया। डॉ. हमीद नुरु, प्रतिनिधि और कंट्री डायरेक्टर, डब्ल्यूएफपी ने आरंभिक भाषण दिया। भारत में संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक और यूएनडीपी के निवासी प्रतिनिधि श्री यूरी अफानासीव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया। डॉ. पी. के. आनंद, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया। विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

भारत सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार मुख्य भाषण देते हुए।

नए नैदानिक परीक्षण नियम, 2018 के मसौदे पर हितधारक परामर्श

आरआईएस के नीतिगत अनुसंधान के तहत यह जानने की कोशिश की जा रही है कि कैसे उभरता भारत अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने, उत्पादन श्रृंखला को आगे बढ़ाने और अपनी अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी का विस्तार करने के लिए वैश्विक मंच पर अपनी तुलनात्मक बढ़त से लाभ उठा सकता है। इसके मद्देनजर आरआईएस ने मसौदा नियमों पर हितधारकों के विचारों से अवगत होने के लिए 7 अप्रैल 2018 को नए नैदानिक परीक्षण नियम, 2018 के मसौदे पर एक पूर्ण दिवस विशेषज्ञ परामर्श का आयोजन किया, ताकि पिछले संशोधनों और देश में नैदानिक परीक्षणों पर इन परिवर्तनों के असर को ध्यान में रखते हुए इन नियमों की जांच एवं आकलन करने के साथ–साथ उन पर चर्चा भी की जा सके।

इस तरह के परामर्श का आयोजन अपने–आप में अनूठा था। इस आयोजन से शैक्षणिक क्षेत्र, उद्योग जगत, निजी एवं सार्वजनिक अनुबंध अनुसंधान संगठनों, नैतिकता समितियों, मीडिया और सरकार की ओर से विविध हितधारकों को एक मंच पर लाना संभव हो पाया। इससे चर्चा के दौरान मौजूद विभिन्न प्रतिभागियों की ओर से विभिन्न दृष्टिकोणों को साझा करने और आदान–प्रदान करने में मदद मिली। दिन भर चले परामर्श को चार तकनीकी सत्रों में बांट कर मसौदा नियम, 2018 के बुनियादी पहलुओं को कवर किया गया। इनमें डेटा सृजन, डेटा उपलब्धता एवं पारदर्शिता, सामंजस्य के मुद्दे, क्षमता निर्माण, अकादमिक एवं उद्योग अनुसंधान संवाद (इंटरफेस), अच्छी नैदानिक एवं प्रयोगशाला प्रथाएं, प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा जैसे पहलू शामिल थे।

इस परामर्श आयोजन का आरम्भ आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ हुआ। उद्घाटन भाषण प्रो. समीर ब्रह्मचारी, पूर्व महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने दिया। विशेष भाषण प्रो. डी. प्रभाकरन, उपाध्यक्ष, भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन (पीएचएफआई) और डॉ. नंदिनी एम कुमार, पूर्व उप महानिदेशक (सीनियर ग्रेड), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा दिए गए। प्रो. टी सी जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने परामर्श के दौरान विचार–विमर्श किए जाने वाले मुद्दों को प्रस्तुत किया। अन्य वक्ताओं में ये शामिल थेः राजदूत सुधीर टी देवारे, अध्यक्ष, शोध सलाहकार परिषद, आरआईएस; डॉ. जाकिर थॉमस, पूर्व निदेशक (ओएसडीडी), सीएसआईआर; प्रोफेसर वैद्य के एस धीमान, महानिदेशक, सीसीआरएएस, आयुष मंत्रालय; डॉ. सरदिन्दु भादुड़ी, अध्यक्ष, सीएसएसपी, जेएनयू; डॉ. चिराग त्रिवेदी, अध्यक्ष, इंडियन सोसायटी फॉर क्लिनिकल रिसर्च; और श्री अशोक मदन, आईडीएमए। परामर्श का समापन आरआईएस की विजिटिंग फेलो डॉ. आभा जायसवाल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। परामर्श के आधार पर आरआईएस ने मसौदे के नियमों पर बिंदुवार टिप्पणियां तैयार की हैं और इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के समक्ष विचारार्थ पेश किया है।

नए नैदानिक परीक्षण नियम, 2018 के मसौदे पर आयोजित हितधारक परामर्श के दौरान अनेक हितधारक।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (स्टिप) फोरम व्याख्यान श्रृंखला

स्टिप फोरम व्याख्यान श्रृंखला के एक हिस्से के रूप में ज्ञान अर्थव्यवस्था के निर्माण में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर नौवां स्टिप व्याख्यान 19 जून 2018 को नई दिल्ली में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार एवं एसएसी–सी के अध्यक्ष प्रोफेसर के. विजय राघवन ने दिया। राजदूत भास्कर बालाकृष्णन, पूर्व भारतीय राजनयिक और विज्ञान कूटनीति फेलो, आरआईएस ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रोफेसर के. विजय राघवन 28 जनवरी, 2013 से 2 फरवरी, 2018 तक भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के सचिव थे। वह इंडियन साइंस एकेडेमिक्स, द रॉयल सोसायटी, द एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (यूके) के फेलो और यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक विदेशी एसोसिएट हैं। उन्हें वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

डॉ. भास्कर बालाकृष्णन आरआईएस में एक विज्ञान कूटनीति फेलो हैं। वह एक करियर राजनयिक रहे हैं और उन्होंने ग्रीस, क्यूबा, हैती एवं डोमिनिकन गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है तथा इसके साथ ही उन्होंने सूडान, सीरिया, जाम्बिया और ऑस्ट्रिया में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय के निवेश एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन प्रभाग की अध्यक्षता संभाली। जैसा कि पहले बताया गया था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (स्टिप) फोरम बनाया गया है। यह फोरम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की अंतर–संबद्ध ता को ध्यान में रखते हुए तय सीमाओं से परे जाकर काम करने में सक्षम है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रचार करने के साथ–साथ सामाजिक आकांक्षाओं की बहस को सामान्य बनाने और जिम्मेदार शोधों एवं नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और समाज के बीच की खाई को पाटना है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति पर सार्वजनिक बहस के प्रति जागरूक करने के लिए मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू की गई है। विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), ऊर्जा संसाधन संस्थान (टेरी), विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई), उन्नत अनुसंधान के संवर्धन के लिए भारत–फ्रांस क्रेद्र (सीईएफआईपीआरए), विज्ञान प्रसार और भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी) सहयोगी संस्थान हैं।

प्रोफेसर के. विजय राघवन स्टिप व्याख्यान देते हुए।

आरआईएस में प्रतिनिधिमंडलों का आगमन

- किसानों के वैश्विक फोरम से जुड़े श्री ए.के. दीक्षित, श्री शशांक, श्री जे. एन. एल. श्रीवास्तव, प्रो. आर.बी. सिंह और डॉ. के. वी प्रभु ने एक संवादात्मक सत्र के लिए 16 अप्रैल 2018 को।
- अफगान सरकार के 20 अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने व्यापार नीति तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक संवादात्मक सत्र के लिए 19 अप्रैल 2018 को।
- इंडोनेशिया के श्री टेउकू कट महमूद अजीज, एस. फिल और श्री इचसान की एक शोध टीम ने कनेक्टिविटी बढ़ाने और आर्थिक सहयोग के साथ–साथ दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने पर एक संवादात्मक सत्र के लिए 19 अप्रैल 2018 को।
- एडीबी की एक टीम, जिसमें श्री रोनाल्ड एंटोनियो बुटियोंग, निदेशक, एसएआरसी; श्री हो यू जियोंग, प्रधान अर्थशास्त्री , एसएआरसी; श्री तादातेरू हायाशी, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, एसएआरसी; श्री मसातो नाकाने, अर्थशास्त्री, एसएआरसी और श्री सौम्य चट्टोपाध्याय, सलाहकार, एडीबी शामिल थे, ने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने और भारत की द्विपक्षीय पहलों एवं एडीबी के क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम के बीच संभावित तालमेल के लिए 26 अप्रैल 2018 को।
- श्री अरिफी सैमन, प्रमुख और सुश्री अर्नावती, उप प्रमुख, एशिया एवं अफ्रीकी क्षेत्र का नीतिगत विश्लेषण और विकास केंद्र, इंडोनेशिया गणराज्य का विदेश मंत्रालय, ने अक्टूबर 2018 में प्रस्तावित आईओआरए, त्रिकोका में इंडोनेशिया की भूमिका पर बातचीत के लिए 21 मई 2018 को।
- श्री गेरब्रांड हेवर कैंप, कार्यकारी निदेशक, इंडेक्स इनीशिएटिव, नीदरलैंड ने 24 मई 2018 को।
- श्री अश्विनी मुथू, निदेशक, वैश्विक सहभागिता एवं बहुपक्षीय संबंध प्रभाग और सुश्री राशा उमर, देश प्रतिनिधि, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि (आईएफएडी) ने भारत–आईएफएडी दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग साझेदारी पर आरआईएस संकाय के साथ विचार–विमर्श के लिए 29 जून 2018 को।

भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के वैश्विक संवर्धन पर उद्योग परामर्श

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा फोरम (एफआईटीएम) ने आयुष मंत्रालय और आरआईएस के सहयोग से 18 मई 2018 को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के वैश्विक संवर्धन पर उद्योग परामर्श का आयोजन किया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य नीतिगत कदम संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए उद्योग जगत और सरकार के बीच संवाद सुनिश्चित करना था। पैनलिस्टों में उद्योग एवं शैक्षणिक जगत और भारत सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल थे। परामर्श के दौरान चर्चाएं प्रतिभागियों के व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित थीं।

परामर्श का उद्घाटन सत्र प्रगति पर।

भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के वैश्विक संवर्धन के मार्ग में मौजूद चुनौतियों की पहचान करने और उपयुक्त समाधान ढूंढ़ने के लिए परामर्श के दौरान चार प्रमुख पैनल परिचर्चाएं आयोजित की गईं। घरेलू नीति एवं निर्यात को बढ़ावा देने पर नियामकीय तैयारियों की समीक्षा; अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण मानकों के लिए उपाय एवं अधिक से अधिक वैज्ञानिक सत्यापन के जरिए गुणवत्ता आश्वासन तथा फार्माकोपिया मानकों का अभिदान; औषधीय पौधों के संग्रह एवं खेती सहित कच्चे माल की आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां; और भारत एवं विदेश में चिकित्सकों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए वेलनेस उद्योग से जुड़े नियम तथा आईएसएम क्षेत्र पर द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संधि और समझौतों का असर इन परिचर्चाओं के विषयों में शामिल थे।

स्वागत भाषण प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने दिया, भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के लिए विजन का अवलोकन श्री राजीव खेर, पूर्व वाणिज्य सचिव एवं प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस द्वारा प्रस्तुत किया गया और डॉ. आकाश तनेजा, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, डीजीएफटी ने मुख्य भाषण दिया। आयुष मंत्रालय के सलाहकार डॉ. मनोज नेसारी ने इस परामर्श का उद्घाटन किया। आयुष मंत्रालय में सचिव श्री वैद्य राजेश कोटेचा और आयुष मंत्रालय में अपर सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक भी इस परामर्श में शामिल हो गए। प्रो. टी.सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के वैश्विक संवर्धन के मार्ग में मौजूद चुनौतियों की पहचान करने और उपयुक्त समाधान ढूंढ़ने के लिए परामर्श के दौरान चार पैनल परिचर्चाएं आयोजित की गईं जिनमें उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। घरेलू नीति एवं निर्यात को बढ़ावा देने पर नियामकीय तैयारियों की समीक्षा; अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण मानकों के लिए उपाय एवं अधिक से अधिक वैज्ञानिक सत्यापन के जरिए गुणवत्ता आश्वासन तथा फार्माकोपिया मानकों का अभिदान; औषधीय पौधों के संग्रह एवं खेती सहित कच्चे माल की आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां; और भारत एवं विदेश में चिकित्सकों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए वेलनेस उद्योग से जुड़े नियम तथा आईएसएम क्षेत्र पर द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संधि और समझौतों का असर इन परिचर्चाओं के विषयों में शामिल थे। परामर्श के आधार पर सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए आयुष मंत्रालय को प्रस्तुत की गई।

'आईओआरए और ब्रिक्स की दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता: शिखर सम्मेलनों में उठाए गए मुद्दों' पर परिचर्चा

आरआईएस और पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने 4 अप्रैल 2018 को यूनेस्को मदनजीत सिंह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संस्थान, पांडिचेरी विश्वविद्यालय में 'आईओआरए और ब्रिक्स की दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता: शिखर सम्मेलनों में उठाए गए मुद्दों' पर संयुक्त रूप से परिचर्चा आयोजित की।

प्रोफेसर गुरमीत सिंह, कुलपति, पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम से पहले डॉ. एस.के. मोहंती, प्रोफेसर, आरआईएस ने आरंभिक भाषण दिया। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग के उप महानिदेशक डॉ. अनिल सुकलाल ने विशेष भाषण दिया। इसके बाद भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायोग के उच्चायुक्त माननीय डॉ. एन.मांजिनी; और श्री आलोक ए. डिमरी, संयुक्त सचिव (एमईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने भाषण दिए। इसके पश्चात बातचीत का दौर चला। डॉ. ए. सुब्रमण्यम राजू, प्रमुख, दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र और समन्वयक, समुद्री अध्ययन के लिए यूजीसी केंद्र, पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत और प्रथाओं पर आरआईएस–एक्जिम बैंक समर स्कूल

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में काम कर रहे विद्वानों के क्षमता निर्माण में योगदान देने के लिए आरआईएस ने भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के सहयोग से 11–16 जून, 2018 को नई दिल्ली में ग्रीष्मकालीन स्कूल कार्यक्रम का तीसरा संस्करण आयोजित किया। इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञता कर रहे एम.फिल और पीएचडी विद्यार्थियों के लिए किया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में आरआईएस ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं, व्यापक आर्थिक सहयोग की संरचना और दक्षिण–दक्षिण सहयोग जैसे क्षेत्रों से जुड़े अनुसंधान एवं नीति में अपने अहम योगदान के लिए विशिष्टता एवं प्रसिद्धि हासिल की है। व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के मुद्दे दरअसल किसी भी संस्थान की मूल विशेषज्ञता को परिभाषित करते हैं जिससे कई शोध अध्ययनों और विचार–विमर्श का मार्ग प्रशस्त होता है।

एक्जिम बैंक भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को वित्त पोषित करने, सुविधाजनक बनाने और इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया देश का प्रमुख निर्यात वित्त संस्थान है। आर्थिक अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के अपने सतत प्रयासों के एक हिस्से के रूप में एक्जिम बैंक ने विद्वानों को विशेषकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित आर्थिक शोध अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक पहल की हैं।

विशेषज्ञों द्वारा पाठ्यक्रम के दौरान इन मापांक (मॉड्यूल) पर विस्तृत चर्चा हुई: 1: व्यापार सिद्धांत में हाल के घटनाक्रम; 2: व्यापार विश्लेषण के साधन एवं प्रौद्योगिकियां; 3: एफटीए और क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉकों को समझना; 4: प्रौद्योगिकी में व्यापार के मुद्दे एवं वर्गीकरण मुद्दे; 5: व्यापार एवं विकास: आईपीआर एवं नए मुद्दे; और 6: समूह प्रस्तुतियां।

कार्यक्रम का आरम्भ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक और प्रो. एस.के. मोहंती, आरआईएस के स्वागत भाषण के साथ हुआ। श्री देबाशीष मल्लिक, उप प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात–आयात बैंक; श्री राजीव खेर, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस; और प्रोफेसर रूपा चंदा, कार्यालय प्रमुख, दक्षिण एवं दक्षिण–पश्चिम एशिया के लिए उप क्षेत्रीय कार्यालय, यूएनएस्कैप ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। प्रतिभागियों में भारत के 24 अभ्यर्थी और बिम्सटेक देशों के 5 अभ्यर्थी शामिल थे। अनुसंधान संस्थानों के प्रमुख विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों को व्याख्यान देने और प्रतिभागियों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

आरआईएस संकाय के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत और प्रथाओं पर आरआईएस–एक्जिम बैंक समर स्कूल के प्रतिभागी।

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रो. सविन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- चेन्नई में 2 अप्रैल, 2018 को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित आईबीएसए शेरपाओं की बैठक में 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग में आईबीएसए की भूमिका' पर एक प्रस्तुति दी।
- 6 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा प्रो. वी.वी. कृष्णा की हालिया संपादित पुस्तक '*यूनिवर्सिटीज इन द नेशनल इनोवेशन सिस्टम*' पर आयोजित पैनल परिचर्चा में भाग लिया।
- 9 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) सम्मेलन में भाग लिया।
- 10 अप्रैल 2018 को अगरतला में नीति आयोग द्वारा आयोजित 'पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम' से जुड़ी पूर्वोत्तर परिषद की पहली बैठक में भाग लिया।
- 11 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय समुद्र तटवर्ती से जुड़ी मसौदा समिति' की उद्घाटन बैठक में एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- लिस्बन में 17–18 अप्रैल 2018 को ' त्रिकोणीय सहयोग के मूल्य वर्द्धित का सर्वोत्तम उपयोग करने' पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय बैठक में 'अहम वैश्विक चुनौतियों को सुलझानाः त्रिकोणीय विकास सहयोग की भूमिका' पर एक प्रस्तुति दी, जिसे 17 अप्रैल 2018 को लिस्बन में कैमियोज – इंस्टीट्यूट दा कोऑपेराकाओ ई दा लिंगुआ और ओईसीडी विकास सहयोग निदेशालय (डीसीडी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।
- 25 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में पैरवी, मौसम, एपीआरएन, एपीआरसीईएम, सेकोईडेकॉन, फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ और ईटीसी समूह द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'सतत एवं समावेशी विकास में बड़ी तकनीक की भूमिका और उत्तरदायित्व' पर राष्ट्रीय परामर्श के दौरान 'सतत एवं समावेशी विकास में बड़ी तकनीक की भूमिका और उत्तरदायित्व' पर एक प्रस्तुति दी।
- 2 मई 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान (एनआईएपी) के वार्षिक दिवस समारोह में 'विज्ञान की केन्द्रीयता, सामाजिक लक्ष्य और कृषि क्षेत्र में आरएंडडी को प्राथमिकता देने' पर डॉ. दयानाथ झा स्मृति व्याख्यान दिया।
- नई दिल्ली में 2 मई 2018 को नीति आयोग द्वारा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति में 'भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था रणनीति की ओरः उभरते अवसरों और चुनौतियों' पर आयोजित एक बैठक में भाग लिया।
- 17 मई 2018 को उदयपुर में सेवा मंदिर द्वारा आयोजित सेवा मंदिर की कार्यकारी परिषद की बैठक में एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 21 मई 2018 को नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा विश्व संस्कृति दिवस के अवसर पर आयोजित 'सॉफ्ट पावर कूटनीति, भारत की ताकत' पर भारत सरकार की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा दिए गए प्रथम पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्मृति अंतर्राष्ट्रीय भाषण में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 23 मई 2018 को भारत–आसियान सामरिक साझेदारी और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पर आयोजित सिविल सोसायटी परामर्श में 'भारत के विकास सहयोग एवं भारत–आसियान सामरिक साझेदारी में सिविल सोसायटी की सहभागिता और एआईआईबी'पर एक प्रस्तुति दी।
- जोहान्सबर्ग में 28 मई 2018 को साउथ अफ्रीकन ब्रिक्स थिंक टैंक्स (एसएबीटीटी) और राष्ट्रीय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल (बीटीटीसी) की बैठक में भाग लिया।
- 29 मई 2018 (स्काइप के माध्यम से) को बैंकाक में कृषि अनुसंधान संस्थानों के एशिया–प्रशांत संघ (एपीएएआरआई) द्वारा 'कृषि जैव प्रौद्योगिकी – एशिया–प्रशांत क्षेत्र में किसानों की आजीविका में बेहतरी लाने के लिए साझेदारी की संभावनाएं ढूंढ़ने' पर आयोजित क्षेत्रीय विशेषज्ञ परामर्श में 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए कृषि जैव प्रौद्योगिकी' पर एक प्रस्तुति दी।
- जोहान्सबर्ग में 29 मई 2018 को साउथ अफ्रीकन ब्रिक्स थिंक टैंक्स (एसएबीटीटी) और राष्ट्रीय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स एकेडेमिक फोरम 2018 में 'ब्रिक्स में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की ओर' पर एक प्रस्तुति दी।
- जोहान्सबर्ग में 30 मई 2018 को साउथ अफ्रीकन ब्रिक्स थिंक टैंक्स (एसएबीटीटी) और राष्ट्रीय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स एकेडेमिक फोरम 2018 में 'सुगम्यं वैश्विक दक्षिण ज्ञान की ओर' पर एक प्रस्तुति दी।
- 4 जून 2018 को गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'भारत की उभरती वैश्विक सहभागिताः शैक्षणिक और अनुसंधान समुदाय की भूमिका' पर सिक्किम विश्वविद्यालय के छात्रों को व्याख्यान दिया।
- सोनीपत में 15 जून 2018 को विजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित पॉलिसी बूट कैंप 2018 में 'उभरती ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएंः अवसरों और चुनौतियों' पर एक प्रस्तुति दी।
- 19 जून 2018 को मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका द्वारा आईपी, खाद्य कानून और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर आयोजित पैनल परिचर्चा के दौरान ''नवाचारों एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में कारगर एसएंडटी नीतियों और क्षेत्रीय सहयोग की भूमिका' पर एक प्रस्तुति दी।
- 27 जून 2018 को यूएनओएसएससी, बैंकॉक द्वारा ' एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण–दक्षिण सहयोगः ब्यूनस आयर्स कार्य योजना की 40वीं वर्षगांठ की ओर' पर आयोजित क्षेत्रीय परामर्श के दौरान ''दक्षिण–दक्षिण सहयोग में नई संभावनाएं ढूंढ़ने' पर एक प्रस्तुति दी।

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रो. एस. के. मोहंती

- 2 अप्रैल 2018 को चेन्नई में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित ' आईबीएसए शेरपाओं की पहली बैठक' में 'आईबीएसए देशों के बीच नीली अर्थव्यवस्था संबंधी त्रिपक्षीय सहयोग' पर एक प्रस्तुति दी।
- 6 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित 'भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते' पर भारत–मॉरीशस सीईसीपीए की बैठक के चौथे दौर से पहले की बैठक में भाग लिया।
- 16 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा 'भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते' पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया।
- 17–19 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित 'भारत–मॉरीशस सीईसीपीए की चौथी बैठक' में भाग लिया।
- 20 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा 'व्यापार और निवेश में लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई देशों के साथ भारत की सहभागिता' पर संयुक्त रूप से आयोजित बहु–हितधारकों की परामर्श बैठक में 'एलएसी के साथ भारत की सहभागिताः व्यापार और निवेश' पर एक प्रस्तुति दी।
- 26 अप्रैल 2018 को नीति आयोग, नई दिल्ली में आयोजित 'ब्लू इकोनॉमी पर मसौदा समिति की दूसरी बैठक' में भाग लिया।
- 2 मई 2018 को नीति आयोग, नई दिल्ली में 'भारत में ब्लू इकोनॉमी के लिए एक रोडमैप और बहुक्षेत्रीय हितधारक के लिए एक एकीकृत महासागर नीति' पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 2 मई 2018 को नीति आयोग, नई दिल्ली में 'भारत में ब्लू इकोनॉमी के लिए एक रोडमैप और बहुक्षेत्रीय हितधारक के लिए एक एकीकृत महासागर नीति' पर आयोजित बैठक में भाग लिया और 'भारत के लिए एक ब्लू इकोनॉमी रणनीति की ओरः उभरते अवसरों और चुनौतियों' पर एक प्रस्तुति दी।
- 11 जून 2018 को नीति आयोग, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया और 'राष्ट्रीय समुद्री नीति' पर एक प्रस्तुति दी।
- 12 जून 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित 'भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (सीईसीपीए) पर समीक्षा बैठक' में भाग लिया।
- 27 जून 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया और 'भारत–मॉरीशस सीईसीपीए जेएसजी' पर एक प्रस्तुति दी।

प्रो. टी.सी. जेम्स

विजिटिंग फेलो

- 17 अप्रैल, 2018 को एनआईपीओ और कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विश्व आईपी दिवस संगोष्ठी में भाग लिया। इस संगोष्ठी का विषय 'मानव अधिकार (एचआर) और महिला–पुरुष' था। 'आईपीआर और एचआर – महिला–पुरुष परिप्रेक्ष्य' पर एक प्रस्तुति दी।
- 20 अप्रैल, 2018 को लॉ सेंटर – आई, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कॉपीराइट प्रवर्तन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉपीराइट और उसके प्रवर्तन पर पैनल परिचर्चा में भाग लिया।
- 20–21 अप्रैल, 2018 को भारतीय कानून संस्थान, नई दिल्ली द्वारा 'बौद्धिक संपदाः प्रक्रिया और अमल' पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र में व्यांख्यान दिया और इसकी अध्यक्षता की।
- 24 अप्रैल 2018 को बौद्धिक संपदा कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित विश्व आईपी दिवस कार्यक्रम में 'आईपीआर– महिला–पुरुष परिप्रेक्ष्य' पर एक प्रस्तुति दी।
- 10 मई, 2018 को विदेश मंत्रालय और भारतीय कानून संस्थान द्वारा आयोजित संगोष्ठी में 'भारत में भौगोलिक संकेतों और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण' विषय पर म्यांमार के विधि अधिकारियों को संबोधित किया।
- 29 मई, 2018 को केआईईटी, गाजियाबाद में कॉपीराइट संरक्षण के महत्व पर व्याख्यान दिया।
- 23 जून 2018 को कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 'विधि शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स" में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया और भौगोलिक संकेतों के सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर दो व्याख्यान दिए।
- 25 जून, 2018 को निलांबर सागवान के विपणन से जुड़े मुद्दों पर निलांबर सागवान उत्पादक संघ के साथ बातचीत की और भौगोलिक संकेत के रूप में निलांबर सागवान के पंजीकरण की दिशा में आगे की कार्रवाई पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया।

डॉ. के. रवि श्रीनिवास

सलाहकार

- 25 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में सतत और समावेशी विकास में बड़ी प्रौद्योगिकी की भूमिका और उत्तरदायित्व पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श के दौरान 'कौन हमारे जलवायु को ठीक करना और हमारे दोपहर के भोजन को खाना चाहता है ' के बारे में कृत्रिम जीवविज्ञान की ताजा स्थिति और बहस पर एक प्रस्तुति दी।

डॉ. प्रियदर्शी दाश

सहायक प्रोफेसर

- 14–15 अप्रैल, 2018 को इथियोपिया के अदीस अबाबा में आयोजित टी20 अफ्रीका स्थायी समूह की वार्षिक बैठक में 'अफ्रीका में व्यापार एवं निवेशः सीएफटीए और आगे की राह' पर नीतिगत संक्षिप्त प्रस्तुत किया।

डॉ. सब्यसाची साहा

सहायक प्रोफेसर

- नई दिल्ली में 06 जून 2018 को एसडीजी पर आयोजित ओआरएफ–जीआईजेड कार्यशाला में 'प्रौद्योगिकी की भूमिका, डिजिटलीकरण, टीएफएम और एसडीजी 17' पर व्याख्यान दिया।
- चीन के शंघाई में 28–29 मई 2018 को आयोजित एनडीबी की वार्षिक बैठक में भाग लिया।

नवीनतम प्रकाशन

पुस्तक / रिपोर्ट

बुनियादी ढांचे हेतु वित्त जुटाने के लिए नई तलाश
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

एआईआईबी की वार्षिक बैठक 2018 मेजबान देश में सेमिनार पृष्ठभूमि–पत्र
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

कनेक्टिविटी कॉरिडोर के आर्थिक प्रभावों का आकलन करना: एक अनुभवजन्य विवेचन
प्रबीर डे, सुनेत्र घटक और दुरइराज कुमारसामी, आरआईएस और आरआईएस स्थित एआईसी, 2018

वैश्विक संदर्भ में भारत–रूस संबंध
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

विकास सहयोग समीक्षा (डीसीआर)

खंड 1 संख्या 1, अप्रैल 2018
खंड 1 संख्या 2, मई 2018
खंड 1 संख्या 3, जून 2018

आरआईएस चर्चा पत्र

227 ब्राजील, चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका में प्रौद्योगिकी विकास नीतियां, मनमोहन अग्रवाल, अमृता ब्रह्मो और जॉन व्हेली

226 सौर ऊर्जा का वित्त पोषण: भारतीय अनुभव से सबक, अमितेन्दु पालित

225 राष्ट्रमंडल और सतत विकास के लक्ष्य, बालाकृष्ण पिसुपति

224 राष्ट्रमंडल महिला और विकास साझेदारियां, अनुराधा एम. चेनॉय

223 एक सच्चा जन राष्ट्रमंडल: सामान्य भविष्य की ओर, राजेश टंडन और कौस्तुव कांति बंद्योपाध्याय

साउथ एशिया इकोनॉमिक जर्नल

खंड 19, संख्या 1 (जनवरी–जून 2018)

एफआईटीएम का नीतिगत संक्षिप्त

पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय की पहुंच एवं विस्तार और नवाचारों के लिए प्रोत्साहन देना, आरआईएस, संख्या 1, नई दिल्ली, 2017

एफआईटीएम का स्कूपिंग पेपर

#1 टीसीएम के राष्ट्रीय और वैश्विक संवर्धन के लिए चीन की नीतिगत पहल द्वारा टी.सी. जेम्स और नम्रता पाठक

आरआईएस डायरी

खंड 14 संख्या 2, अप्रैल 2018

आरआईएस संकाय द्वारा बाह्य प्रकाशनों में योगदान

चतुर्वेदी, सचिन. 2018. *'आर्थिक विकास और सहयोग'* । नेपाल–भारत संबंधों पर तीन दिवसीय द्विपक्षीय सेमिनार की कार्यवाही, 3–5 मार्च, 2017, सिमारा, नेपाल।

चतुर्वेदी, सचिन 2018. *नेपाल– भारत संबंधों में 'व्यापार, पारगमन और आपूर्ति': आर्थिक विकास और सहयोग*, 3–5 मार्च, 2017 को तीन दिवसीय द्विपक्षीय सेमिनार की कार्यवाही, सिमारा, नेपाल।

चतुर्वेदी, सचिन. 2018. व्यापार युद्ध: शुल्कों (टैरिफ) द्वारा पछाड़ा गया – यह अमेरिका नहीं है जो वैश्विक व्यापार आदेश का शिकार बना है; यह भारत है। *द वीक*, 01 जुलाई, 2018।

चतुर्वेदी, सचिन. 2018. 'लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एसडीजी का स्थानीयकरण करें।' फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 15 जून 2018।

प्रबीर डे और सुथिपंद चिरथिवत. 2018. *तीसरे दशक का जश्न मनाना और उससे परे: आसियान– भारत आर्थिक साझेदारी के लिए नई चुनौतियां,* रूटलेज, नई दिल्ली, 2018 (संपादक और लेखक)।

प्रबीर डे. 2018. 'लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की ओर: तीसरे दशक में आसियान–भारत साझेदारी को नया स्वरूप देना' रुमेल दहिया और उदय भानु सिंह (संपादक) *आसियान–भारत संबंध: एक नया प्रतिमान,* आईडीएसए, नई दिल्ली।

प्रबीर डे. 2018. "आसियान–भारत मूल्य श्रृंखला के लिए कनेक्टिविटी का निर्माण करना हर्ष वी. पंत (संपादक) *अगले 25 वर्षों के लिए भारत–आसियान संबंधों की दिशा तय करना*। ओआरएफ, नई दिल्ली।

दुरइराज कुमारसामी. 2018. 'दक्षिण और पूर्वी एशिया को एकीकृत करना: क्षेत्रीय सहयोग और विकास के अर्थशास्त्र' पर पुस्तक समीक्षा, द्वारा जयंत मेनन और टी.एन. श्रीनिवासन (संपादक), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2018, पृष्ठ 397, *साउथ एशिया इकोनॉमिक जर्नल* में, खंड 19, संख्या 1, पृष्ठ 140–143।

श्रीनिवास, रवि के. 2018. "भारत में स्वास्थ्य प्रभाव कोष के माध्यम से दवाओं तक पहुंच बढ़ाना: एक हितधारक विश्लेषण। पैट्रिक मैकमुल्लन, वामादेवन एस. अजय, रवि श्रीनिवास, संदीप भल्ला, दोरइराज प्रभाकरन और अमिताभ बनर्जी (संपादक) *ग्लोबल हेल्थ एक्शन,* 11:1, 1434935, डीओआई: 10. 1080 / 16549716.2018.143493.

श्रीनिवास, रवि के. 2018. 'हालिया: 'संघर्षरत शासन व्यवस्थाएं: पहुंच एवं लाभ साझाकरण पर विवाद और वायरस के नमूनों को साझा करना '। *यूरोपियन जर्नल ऑफ रिस्क रिसर्च* (ईजेआरआर) (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस) खंड 8, पृष्ठ, 573–579

RIS
Research and Information System for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4-बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003, भारत । दूरभाष: 91-11-24682177-80
फैक्स: 91-11-24682173-74, ई-मेल: dgoffice@ris.org.in
वेबसाइट: http://www.ris.org.in

Follow us on:
www.facebook.com/risindia @RIS_NewDelhi www.youtube.com/RISNewDelhi

क्षेत्रवार और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो संस्थागत वित्त

प्रो. अमिताभ कुंडू
प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस

वंडरलैंड में एलिस इधर–उधर भटक रही थी और इस दौरान रहस्यमय परिवेश से टकरा रही थी और इसके साथ ही विभिन्न प्रजातियों के असाधारण दिखने वाले सदस्यों से गुफ्तगू भी कर रही थी। अचानक, उसे एक मेज पर पीने वाली एक औषधि नजर आती है जिसे वह पी जाती है। इस दवा के असर से वह बेहद लंबी हो जाती है। उसके सिर और पैरों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में वह चिंतित होकर यह सोचने लगती है: 'क्या मैं अब अपने पैरों की समुचित साफ–सफाई कर पाऊंगी जो मुझसे काफी दूर हो गए हैं?' इससे भी ज्यादा चिंतित वह इस विषय को लेकर है कि क्या मेरे पैर अब मेरे आदेश का पालन करेंगे? क्या मैं जिस दिशा में उन्हें चलाना पसंद करूंगी, उसी दिशा में वे चलेंगे? इसलिए, वह निर्णय लेती है मैं उन्हें हर क्रिसमस पर जूते की एक नई जोड़ी दूंगी, ताकि उन्हें प्रसन्न और आज्ञाकारी बनाए रखा जा सके।

लेविस कैरोल द्वारा अपने फंतासी उपन्यास में गढ़े गए इन काल्पनिक चित्रों का उद्देश्य उस गलतफहमी और समुचित तालमेल एवं अनुपालन के अभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना है जो अक्सर किसी चीज के मूल भाग या केन्द्र एवं इसकी परिधि के बीच विद्यमान रहते हैं और जो लंबी दूरी के कारण एक–दूसरे से काफी अलग या दूर रहते हैं। भले ही ये दोनों एक ही इकाई का हिस्सा हों, लेकिन ये लाभों के वितरण में असमानता उत्पन्न कर सकते हैं और इस वजह से 'असमान या वंचित रखने वाले विकास' की स्थिति बन सकती है।

भारत में क्षेत्रीय असमानता दरअसल 'दूरी' कारक से काफी गहराई से जुड़ी हुई है। दूरी से तात्पर्य केवल भौगोलिक दूरी से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दूरी से भी है। आजादी के समय भारत को एक बेहद असमान क्षेत्रीय ढांचा विरासत में मिला था। वित्त आयोग, योजना आयोग और अन्य संस्थानों द्वारा काफी अच्छी तरह से सोच–समझ कर कई कदम उठाने के बावजूद क्षेत्रीय असमानता कम से कम वर्ष 2007–08 तक बढ़ती चली गई। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के नवगठित राज्यों के साथ बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, जहां आर्थिक विकास की उच्च दर दर्ज की गई है और अनेक पूर्वोत्तर राज्यों, जो ढांचागत पिछड़ेपन के दलदल से उबर चुके हैं, की बदौलत क्षेत्रीय असमानता बढ़ने की प्रवृत्ति या तो थम गई है या कम से कम धीमी तो हो ही गई है। हालांकि, इसके बावजूद क्षेत्रीय असमानता अब भी अत्यधिक है। अल्प विकसित क्षेत्रों और उनके अत्यंत पिछड़े इलाकों के बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में निवेश करने से दूरी संबंधी उलझनों को कम करने और समावेशी विकास के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करने में काफी मदद मिल सकती है। आधुनिक बुनियादी ढांचागत सुविधाओं से तालमेल एवं पारदर्शिता बढ़ती है, निहित स्वार्थों की भूमिका घट जाती है और इसके साथ ही केंद्रीय, राज्य एवं शहर/बस्ती स्तरों पर कार्यरत शासकीय प्रणालियों के आपसी समन्वय के साथ काम करने का मार्ग प्रशस्त होता है।

शोधकर्ताओं ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि भारी उद्योगों, फसल उत्पादन इत्यादि सहित आर्थिक गतिविधियों का स्थानिक वितरण दरअसल संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से इष्टतम नहीं है। इसे औपनिवेशिक इतिहास और औपनिवेशिक काल के बाद अपनाई गई गलत नीतियों के संदर्भ में समझाया गया है। पिछड़े राज्यों की क्षमता का न तो आकलन किया गया है और न ही उसका भरपूर उपयोग किया गया है। इन राज्यों में विकास के हालिया रुझानों को देखते हुए ऐसा कोई भी कारण नजर नहीं आता है कि आने वाले दशकों में उन्हें देश में समग्र आर्थिक विकास प्रक्रिया की अगुवाई क्यों नहीं करनी चाहिए।

क्या हम क्षेत्रीय असमानता की समस्याओं से निजात पाने के लिए सही क्षेत्रों के उचित सेक्टरों में सही निवेश कर रहे हैं? क्या एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी), एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक इत्यादि के निवेश के साथ–साथ व्यक्तिगत निवेशक भी इन सही क्षेत्रों में जाएंगे?

लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारी–भरकम निवेश की आवश्यकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जोखिम थोड़ा अधिक हो सकता है। लगाई गई पूंजी पर रिटर्न पाने में लंबा समय लग सकता है। निवेश पर्याप्त मात्रा में और उपयुक्त समय पर सही क्षेत्रों में हो, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों को क्या करना चाहिए? इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आरआईएस ने फरवरी–जून 2018 के दौरान पूर्वावलोकन समारोह और एआईबीबी की अंतिम वार्षिक बैठक में विभिन्न सत्रों के आयोजन के अलावा आठ विषयगत संबंधित (लीड–अप) कार्यक्रमों के आयोजन की भी चुनौती स्वीकार की। उपयुक्त उप विषयों को तय करके और प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करके देश की विकास संबंधी प्रमुख चिंताओं को चर्चाओं के केंद्र में लाया गया। इन आयोजनों के सटीक आकलन से पता चलता है कि अनुभवजन्य दृढ़ता के साथ इन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयत्न किया गया तथा वित्त मंत्रालय और एआईआईबी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समझे जाने वाली सिफारिशों को प्रस्तुत करना संभव हो सका। आरआईएस को यह आशा है कि केंद्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर भारत में संबंधित मंत्रालयों के साथ–साथ क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों तथा निवेशकों द्वारा भी इन सिफारिशों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक

- पूर्वावलोकन समारोह

संबंधित (लीड–अप) कार्यक्रम

- त्वरित जन परिवहन प्रणालियां
- बंदरगाह और तटीय बुनियादी ढांचा
- शहरी विकास
- अत्याधुनिक, सुदृढ़ और डिजिटल बुनियादी ढांचा
- क्षेत्रीय विकास
- स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा
- जल और स्वच्छता
- संसाधन जुटाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी और नवाचार